आबादी पर मीडिया का दृष्टिकोण

वरुण शैलेश*

जनगणना-2011 के मुताबिक मुस्लिमों की आबादी पिछले दशकों की तुलना में बहुत धीमी गति से बढ़ी है और इनकी वृद्धि दर हिन्दू आबादी के मुकाबले तेजी से कम हुई है। भारतीय जनगणना के इतिहास के एक दशक में मुस्लिमों की वृद्धि दर में सबसे ज्यादा कमी 2011 की जनगणना में हुई है। भारत में पिछले 10 वर्षों में हिंदुओं और मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर में गिरावट आई है। ऐसा भारत में जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर में आई कमी की वजह से हुआ है। ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन की जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई है। जनगणना-2011 के मुताबिक हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर 16.76 फीसदी रही जबकि 10 साल पहले हुई जनगणना में ये दर 19.92 फीसदी पाई गई थी। 2001 में भारत में मुसलमानों की आबादी 29.52 प्रतिशत की दर से बढ़ रही थी जो अब गिरकर 24.6 फीसदी हो गई है। धार्मिक आबादी की गणना के विश्लेषण में जब केवल हिन्दू और मुसलमान आबादी की तुलना करने की पद्धति अपनाई जाती है तो ये दावा किया जा सकता है कि भारत में मुसलमानों की वृद्धि दर अब भी हिंदुओं की जनसंख्या वृद्धि दर से अधिक है। लेकिन यह भी सच है कि मुसलमानों की आबादी बढ़ने की दर में हिंदुओं की तुलना में अधिक गिरावट आई है। ईसाइयों की जनसंख्या वृद्धि दर 15.5 फीसदी, सिखों की 8.4 फीसदी, बौद्धों की 6.1 फीसदी और जैनियों की 5.4 फीसदी है। जनगणना 2011 के आंकड़ों के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी 96.62 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 79.8 फीसदी है। वहीं मुसलमानों की आबादी 17.22 करोड़ है, जो कि जनसंख्या का 14.23 फीसदी है। ईसाइयों की आबादी 2.78 करोड़ है, जो कि कुल जनसंख्या का 2.3 फीसदी और सिखों की आबादी 2.08 करोड़ (2.16 फीसदी) और बौद्धों की आबादी 0.84 करोड़ (0.7 फीसदी) है। 29 लाख लोगों ने जनगणना में अपने धर्म का जिक्र नहीं किया। पिछले एक दशक में किसी धर्म को नहीं मानने वालों की जनसंख्या 17.7 फीसदी की दर से बढ़ी है।

जनगणना का इतिहास और सांप्रदायिकता

जनगणना का एक वैज्ञानिक उद्देश्य है। लेकिन उसका इस्तेमाल विभिन्न तरह की राजनीतिक शक्तियां अपने हितों में करती हैं। भारत में यह धार्मिक और जातीय पहचान पर गहरा प्रभाव छोड़ता है। धार्मिक पहचान की इस कवायद ने संसदीय राजनीति के क्षेत्र में कई आयाम जुड़े हैं। ब्रिटेन में 1801 में पहली जनगणना हुई थी और उसके सात दशक बाद भारत में यह काम पहली बार ब्रिटिशकाल के दौरान वर्ष 1872 में शुरू हुआ। ब्रिटेन के उलट भारत की पहली जनगणना में ही धार्मिक समुदायों की संख्या का सवाल शामिल कर लिया गया था, जबकि इंग्लैंड (ब्रिटेन) में 2001 की जनगणना में आबादी के धार्मिक आंकड़ों के इस पहलू को शामिल किया गया। ब्रिटिशकालीन भारत में जब पहली जनगणना के धार्मिक आंकड़े सामने आए तो तीखी सांप्रदायिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली थी। अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के बाद भी सांप्रदायिक चर्चा में जनसांख्यिकीय मुद्दे प्रमुखता से कायम रहे। औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक भारत में हिन्दू-मुस्लिम चेतना को विकसित करने और दोनों धर्मों के लोगों के बीच रिश्तों को प्रभावित करने में धार्मिक आंकड़ों के प्रकाशन ने बड़ी

तालिका-1 हिन्दू आबादी की दशकीय वृद्धि दर

वर्ष	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
हिन्दू आबादी (करोड़ में)	30.35	36.65	45.33	56.24	69.01	82.76	96.62
वृद्धि दर(% में)	-	20.76	23.68	24.07	22.71	19.92	16.76

(स्रोत-आईआईपीएस इंडिया, भारत की जनगणना के आंकड़े)

तालिका-2 मुस्लिम आबादी की दशकीय वृद्धि दर

वर्ष	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
मुस्लिम आबादी (करोड़ में)	3.54	4.69	6.14	8.13	10.67	13.82	17.22
वृद्धि दर(% में)		32.49	30.92	30.78	32.88	29.52	24.60

(स्रोत-आईआईपीएस इंडिया, भारत की जनगणना के आंकड़े)

भूमिका अदा की। नतीजतन सांप्रदायिक बहसों में कई किस्म के मुस्लिमों के खिलाफ जनसांख्यिकीय मिथकों को जगह दी जाने लगी जिसने देश की राजनीतिक शक्ल को अंजाम दिया।[1]

मिथ को पैबस्त करने की प्रक्रिया

औपनिवेशिक भारत में जब पहली बार धार्मिक जनसांख्यिकीय सामने आया तब से ही, अल्पसंख्यकों खासकर मुस्लिम आबादी को लेकर मिथ तैयार करने की एक प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया में हिन्दुओं के खत्म होने की कहानी बुनी जाने लगी। डिपार्टमेंट ऑफ माइग्रेशन एंड अर्बन स्टडीज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पापुलेशन साइंस, मुंबई के आर.बी. भगत कहते हैं कि जनसंख्या के आंकड़ों के जारी होते ही औपनिवेशक भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी और उनकी वृद्धि दर को लेकर सांप्रदायिक बहस शुरू हो गई। 1891-1901 और 1911-1921 की जनगणना में हिन्दू जनसंख्या की वृद्धि दर में मामूली कमी आई थी। इन आंकड़ों की वजह से हिन्दू-मुस्लिम रिश्तों में खटास पैदा होनी शुरू हुई। 1909 में कलकत्ता के यू.एन. मुखर्जी ने बांग्ला में लेखों की एक श्रृंखला प्रकाशित की। बाद में इन लेखों के संग्रह को एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया जिसका शीर्षक था 'हिन्दूः द डायइंग रेस' यानी हिन्दूः एक मरती हुई कौम। मुखर्जी ने 1901 की जनसंख्या के आंकड़ों का उल्लेख करते हुए हिन्दू आबादी की विकास दर में आई कमी पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की और उन्होंने इस तरह की आशंका को उभारा कि अगले 420 वर्षों में हिन्दू समाप्त हो जाएंगे। मुखर्जी ने उस समय के प्रमुख हिन्दू नेता स्वामी श्रद्धानंद को मुस्लिमों और ईसाइयों का धर्मांतरण कराकर हिन्दू बनाने के लिए उकसाया। स्वामी श्रद्धानंद ने भी 1926 में 'Hindu Sangsthan: Saviour of Dying Race' शीर्षक से एक किताब लिखी। बाद के वर्षों में जनसांख्यिकीय गिरावट का यही विचार हिंदू सांप्रदायिकता की एक प्रमुख विशेषता बन गई। यह जानते हुए कि इन धार्मिक आंकड़ों से भारी सांप्रदायिक मनमुटाव पैदा होगा, इसके बावजूद औपनिवेशिक भारत में इस तरह के जनसांख्यिकीय को सामने लाया गया।[2]

जनगणना और मीडिया

यह प्रक्रिया भारतीय राजनीति में 2015 में भी आकर नहीं ठहरती है बल्कि वक्त के साथ यह और रूढ़ हुई है। इस राजनीतिक स्वरूप को बनाने में संचार माध्यमों की भूमिका बढ़ती चली गई है। विकसित तकनीक के इस्तेमाल से इस प्रक्रिया की गति तेज और विकृत भी हुई है। भारतीय मीडिया अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक निहितार्थों के अनुकूल धार्मिक आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। 25 अगस्त 2015 को गृह मंत्रालय के अधीन महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की ओर से जारी धार्मिक आंकड़ों से पहले भी धार्मिक आंकड़े जनसंचार माध्यमों में आ चुके थे। लोकसभा चुनाव-2014 से पहले ही अंग्रेजी की 'ओपेन' पत्रिका में पी.आर. रमेश ने जनगणना कार्यालय से लीक धार्मिक आंकड़ों के आधार पर 'द अनटोल्ड सेंस्स स्टोरी' की रिपोर्ट पेश की जिसमें मुस्लिम आबादी बढ़ने की बात कही गई। इसी तरह दिल्ली विधानसभा चुनाव-2015 से पहले 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में भारती जैन ने मुस्लिम आबादी को लेकर रिपोर्ट की, जिसे एक दिन बाद समाचार एजेंसी पीटीआई-भाषा ने क्रमशः अंग्रेजी और हिन्दी में जारी किया जो इलेक्ट्रॉनिक, वेब एवं प्रिंट आदि माध्यमों के जरिये प्रचारित-प्रसारित किया गया।[3] धार्मिक, जातिगत पूर्वाग्रहों और राज्य समर्थित मानी जाने वाली खबरों को लेकर कॉपी

तालिका-3 हिंदी अखबारों की खबरों के शीर्षक

अखबार	24 जनवरी 2015	26 अगस्त 2015
जनसत्ता	मुसलमानों की आबादी राष्ट्रीय औसत से छह फीसद ज्यादा बढ़ी।	हिंदू घट गए, मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी
दैनिक जागरण	देश में मुस्लिमों की आबादी 24% बढ़ी	बढ़ी मुस्लिम हिस्सेदारी
दैनिक भास्कर	दस साल में मुस्लिमों की आबादी 24 फीसदी बढ़ी	आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी 0. 8% बढ़ी, हिंदुओं की 0.7%घटी
हिन्दुस्तान	एक दशक में 24% बढ़ी मुस्लिम आबादी	मुस्लिम आबादी सबसे तेज बढ़ी
News headings in English Newspapers		
Newspaper	23-24 January, 2015	26 August, 2015
Times of India	Muslim population grows 24%, but slower than last decade	Muslim share of population up 0.8%, Hindus' down 0.7%
Indian Express	Census: Hindus share dips below 80% Muslim share grows but slower	Hindus dip to below 80% of population; Muslim share up, slows down

नोट- टाइम्स ऑफ इंडिया में 23 जनवरी 2015 को भारती जैन की धार्मिक आंकड़ों पर रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। उसके एक दिन बाद दूसरे अखबारों ने उसी खबर को हू-ब-हू प्रकाशित किया।

राइट की बात और खबरों के पुरानी होने की दलीलें भी बेमानी हो जाती हैं। ऐसी खबरों को प्रसारित करने में एक तरह से मीडिया समूहों में सहमति देखी जाती है और वो एक दूसरे की सामग्री को कई दृष्टिकोण से प्रस्तुत करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव-2015 से पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के साथ यह बात देखी गई।[4] 2014 के दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आए धार्मिक आंकड़ों को लेकर प्रकाशित खबरों के शीर्षक से किस तरह से मुस्लिम आबादी को दुश्मन की सैन्य शक्ति बढ़ने की तरह प्रस्तुत किया गया। (तालिका-3 देखें)

देश में धार्मिक आंकड़ों के किसी भी तरीके से मीडिया में आने के समय को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं। चूंकि भारत में राजनीति का मुख्य आधार जाति और धर्म बन चुका है इसलिए किसी चुनाव से पहले धार्मिक आंकड़ों का जारी होना दक्षिणपंथी राजनीतिकों के लिए एक शस्त्र बन जाता है जिसे लेकर वे ध्रुवीकरण का प्रयास शुरू कर देते हैं।

चुनाव के दौरान और उससे पहले देश के वातावरण में हिन्दुत्व का रंग घोलने का नतीजा देखने के हम आदि हो गए हैं। क्या यह अजीब सी बात नहीं है कि अल्पसंख्यकों को ही साम्प्रदायिक होने के रूप में पेश किया जाता है। ये भी कम दिलचस्प नहीं है कि भारत में संसदीय चुनाव प्रणाली है और 50 वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ कि लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान मुस्लिम प्रतिनिधियों के चुने जाने की दर सबसे कम रही और 22 मुस्लिम सांसद ही चुनकर संसद पहुंच

पाए जो कि पिछली बार से सात कम हैं। जबकि देश में मुस्लिम आबादी के बढ़ने का शोर सबसे ज्यादा होता है। आबादी तो 14 फीसदी है लेकिन उनके संसद प्रतिनिधियों के चुने जाने की दर केवल चार प्रतिशत है। लोकसभा चुनाव 2014 से पहले के 15 वर्षों तक 30 से ज्यादा मुस्लिम सांसद चुने जाते रहे हैं। 1980-89 के दौरान 40 से ज्यादा मुस्लिम प्रतिनिधि चुनकर संसद पहुंचे। भारी जीत हासिल करने वाली भाजपा ने देशभर में केवल पांच मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे थे लेकिन उनमें से एक भी चुनाव नहीं जीत सका। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के आठ मुस्लिम प्रतिनिधि चुने गए।[5]

सकारात्मक पहलू को हतोत्साहित करना

2011 की जनगणना में मुस्लिम पुरुष-महिला के अनुपात में हिन्दू पुरुष-महिला की तुलना में काफी सुधार हुआ है। 2011 की जनगणना में 1000 मुस्लिम पुरुषों के मुकाबले 951 मुस्लिम महिलाओं का अनुपात रहा जबकि 2001 में यह अनुपात 1000 पुरुषों पर 936 महिलाओं का था। वहीं 2011 की जनगणना मामूली सुधार के साथ 1000 हिन्दू पुरुषों पर 936 हिन्दू महिलाएं हैं। 2001 में यह आंकड़ा 1000 पुरुषों पर 931 हिन्दू महिलाओं का था। हिन्दू पुरुष-महिला का अनुपात दोनों दशकों में मुस्लिम पुरुष-महिला अनुपात की तुलना में कम रहा है। पुरुष-महिला अनुपात में ईसाइयों की आबादी दूसरे धर्मावलंबियों की तुलना में बेहतर है। देश में 1.37 करोड़ ईसाई पुरुष हैं वहीं महिलाएं 1.40 करोड़ हैं।[6] असमान लिंगानुपात की स्थिति में ईसाइयों की आबादी दूसरे धर्मावलंबियों के लिए तो मिसाल बन सकती है। लेकिन समाचार पत्रों में इस तथ्य को कमजोर तरीके से पेश किया गया।

मुखपत्र बनाम समाचार पत्र

हिन्दुत्ववादी विचारधारा के संगठन शुरू से ही मुसलमानों की जनसंख्या में विकास दर को सांप्रदायिक नजरिये से प्रस्तुत करते रहे हैं। 25 अगस्त 2015 को महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की ओर से धार्मिक आंकड़ों को जारी किए जाने के बाद हिन्दुत्वादी संगठन विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने बयान जारी कर हिन्दू और मुस्लिम आबादी के अनुपात को असंतुलित बताया। विश्व हिन्दू परिषद ने कश्मीर घाटी, बिहार व बंगाल के तीन तथा असम के नौ मुस्लिम बाहुल्य जिलों में साम्प्रदायिक सद्भाव खत्म होने की बात कही।[7] धार्मिक आंकड़ों के जारी होने के कई दिनों बाद तक इससे संबंधित खबरें छपती रहीं। इन खबरों के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व हिन्दू परिषद की भाषा और समाचार पत्रों की भाषा एवं दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं है। अखबारों के हिन्दुत्वादी संगठनों के मुखपत्र बनने की यह एक प्रक्रिया है। दैनिक जागरण के 27 अगस्त, 2015 के दिल्ली संस्करण के पेज संख्या 19 पर 'सात राज्यों में अल्पसंख्यक हैं हिन्दू' शीर्षक से एक खबर प्रकाशित हुई। दैनिक जागरण के संवाददाता हरिकिशन शर्मा जनगणना कार्यालय के आंकड़ों के जरिये मिजोरम, नगालैंड, मेघालय, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पंजाब में हिन्दुओं के अल्पसंख्यक होने की जानकारी देते हैं।[8] खबर लिखते वक्त संवाददाता इस बात की अनदेखी कर देता है कि ये राज्य या तो आदिवासी, मुस्लिम या सिख बहुल हैं। इन राज्यों में हिन्दुओं की आबादी कभी भी दूसरे समुदायों की तुलना में अधिक नहीं रही है। मिजोरम, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर आदिवासी बहुल राज्य हैं। लेकिन अखबार तुलना करने की पद्धति का इस्तेमाल भी अपने तंग नजरिये को ही पुष्ट करने के लिए करता है। संवाददाता आदिवासी समुदाय की आबादी के बारे में कोई जानकारी नहीं देता है। इसी तरह पंजाब, सिख और जम्मू कश्मीर, मुस्लिम बहुल राज्य है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इन राज्यों में उन्हीं लोगों की आबादी ज्यादा होगी जो वहां के मूल निवासी हैं। दैनिक जागरण ने इसी खबर के साथ एक छोटे से बॉक्स में एक दूसरी खबर चस्पा कर दी है। इसमें गोरखपुर के भाजपा सांसद योगी आदित्यनाथ का बयान है जिसमें वह धार्मिक आंकड़ों को चिंताजनक बताते हुए जनसंख्या नियंत्रण के लिए कठोर कानून और समान अचार संहिता की हिमायत करते हैं। विश्व हिन्दू परिषद के बयान में भी भारत सरकार से कठोर कानून तथा समान अचार संहिता बनाने की अपील की गई है।[9] विश्व हिन्दू परिषद की विज्ञप्ति और समाचार पत्रों की सामग्री में कोई बुनियादी अंतर नहीं। जो बात विहिप अपने बयान में कहता है वही बात दैनिक जागरण में बाइलाइन कही जा रही है। इसमें अब विडंबना जैसी कोई बात नहीं रह गई है कि दैनिक जागरण और विश्व हिन्दू परिषद की प्रेस विज्ञप्ति में कोई अंतर नहीं दिखता है।

आदिवासियों को हिन्दू बताने की साजिश

दैनिक जागरण ने 20 सितंबर 2015 के राष्ट्रीय संस्करण में 'मुस्लिम बहुल नहीं सबसे गरीब जिले' शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की। खबर के शीर्षके के ऊपर एक उपशीर्षक है जिसमें लिखा है कि

'देश के आदिवासी बहुल इलाके सबसे गरीब'। खबर में लिखा गया है कि तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टियां भले ही मुस्लिम बहुल इलाकों को सबसे ज्यादा वंचित बताएं लेकिन हकीकत यह है कि देश के सबसे निर्धन 20 जिलों में एक भी मुस्लिम बहुल नहीं हैं। देश के सर्वाधिक गरीब जिले आदिवासी बहुल हैं। ये जिले ऐसे हैं जहां आधे से अधिक परिवारों के पास कुछ भी संपत्ति नहीं है। यह खुलासा जनगणना-2011 के धार्मिक आंकड़ों के विश्लेषण से हुआ है। खबर में आगे लिखा गया है कि कुल मिलाकर 20 निर्धन जिलों में 1.53 करोड़ आबादी है, जिनमें से 83.23 फीसदी हिंदू हैं, जबकि मुस्लिम मात्र 4.45 फीसदी हैं। उल्लेखनीय है कि देश की कुल आबादी में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 14.23 फीसद है। हालांकि निर्धन जिलों में ईसाइयों की आबादी 9.32 प्रतिशत है। इसकी वजह है कि नगालैंड के मोन, लोंगलेंग, त्यूनसांग और किपरे, मेघालय का वेस्ट खासी हिल्स और अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंट और कुरुंग कुमेय जिले ईसाई बहुल हैं।[10] जागरण ने विभिन्न समुदायों की जनसंख्या का प्रतिशत बताते हुए उन 20 जिलों की सूची भी दी है जो गरीब हैं और आदिवासी बहुल हैं। लेकिन इन जिलों में आदिवासियों की आबादी कितनी है इसका जिक्र कहीं नहीं किया गया है। यह आदिवासियों को हिन्दू बताने का सायास प्रयास है जिसे मुस्लिम विरोध में खड़ा कर दिया गया है। दैनिक जागरण ने इससे पहले 27 अगस्त, 2015 को दिल्ली संस्करण के पेज संख्या 19 पर 'सात राज्यों में अल्पसंख्यक हैं हिन्दू' शीर्षक से प्रकाशित खबर में आदिवासियों की आबादी की अनदेखी करते हुए उन राज्यों में हिन्दुओं को अल्पसंख्यक बताया था, जिस पर उपर्युक्त पैराग्राफ में चर्चा की गई है। दैनिक जागरण की इस कवायद को आदिवासियों को हिन्दू बताने के रूप में देखा जा सकता है।

जनगणना-2011 के आंकड़ों को हिन्दू बनाम मुस्लिम बनाने और आदिवासियों को हिन्दू बताने में सिर्फ हिन्दी अखबारों की भूमिका ही नहीं रही बल्कि जनसंख्या पर संतुलित रिपोर्टिंग करने वाला अंग्रेजी समाचार पत्र 'द हिन्दू' भी पीछे नहीं रहा। 30 अगस्त 2015, को द हिन्दू के कोलकाता संस्करण के पेज संख्या दो पर 'पॉपुलेशन ऑफ क्रिश्चियन ग्रियू बाई 478% इन ओडिशा इन 50 इयर्स' शीर्षक से एंकर स्टोरी छपी। इस खबर में बताया गया कि ओडिशा में पिछले 50 वर्षों में ईसाई की आबादी 478 फीसदी बढ़ी है जबकि हिन्दुओं और मुस्लिमों की जनसंख्या क्रमशः 323 और 130 फीसदी बढ़ी है। यहां ईसाई बनाम हिन्दू-मुस्लिम कर दिया गया। इस खबर में ओडिशा के कई जिलों का ब्यौरा प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि कहां किसकी कितनी आबादी बढ़ी और घटी है। कंधमाल, कटक, भद्रक, गंजम, सुंदरगढ़, जगतसिंहपुर, कालाहांडी और बौद्ध जिले का उल्लेख किया।[11] ओडिशा आदिवासी बहुल राज्य है लेकिन खबर में कहीं भी उनके बारे में जिक्र नहीं है। इस अखबार ने भी आदिवासियों को हिन्दू मान लिया है।

गौर करने की बात है कि जनगणना-2011 में आदिवासी आबादी के बारे में उल्लेख नहीं करने को लेकर देश के कई संगठनों ने इसे साजिश बताते हुए कड़ा विरोध दर्ज कराया था। आदिवासी संगठनों ने महापंजीयक और जनगणना आयुक्त की ओर से प्रकाशित धर्म पर जनगणना के आंकड़ों को त्रुटिपूर्ण और अप्रमाणिक बताया और दावा किया कि रिपोर्ट में 20 करोड़ आदिवासियों को छोड़ दिया गया। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन (अजसू) के संस्थापक अध्यक्ष और झारखंड पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि सरना धर्म संहिता का अलग से कोई उल्लेख नहीं है और 20,13,78000 आदिवासियों के लिए कोई खंड नहीं है जो प्रकृति की पूजा करते हैं।[12]

मुस्लिम बनाम हिन्दू अनुपात

आज के संदर्भ में बात करने से पहले एक तथ्य का उल्लेख जरूरी लगता है। दुनिया के एक मात्र हिन्दू देश के रूप में प्रचारित नेपाल में जनसंख्या की वार्षिक विकास की दर 2.1 प्रतिशत रही है जबकि इस्लामिक राष्ट्र बांग्लादेश में उससे कम दो प्रतिशत। धार्मिक कारणों से यदि जनसंख्या में वृद्धि बताई जा रही है तो फिर जीने की औसत उम्र के लिए भी धार्मिक कारणों को माना जा सकता है। हिन्दू राष्ट्र नेपाल (धर्मनिरपेक्ष) में जहां मात्र 57 वर्ष की औसत उम्र रही है, वहीं इस्लामिक राष्ट्र पाकिस्तान में 70 वर्ष और बांग्लादेश में 58 वर्ष है। असल में, आबादी की समस्या को विभिन्न राजनीतिक शक्तियां अपने सियासी उद्देश्यों के लिए अलग-अलग रूपों में पेश करती हैं। भारत के तमाम धार्मिक अल्पसंख्यक समूहों की जनसंख्या में लगभग समान रूप से बढ़ोतरी हुई है।

किसी भी धार्मिक समुदाय की आबादी की बढ़ोतरी और कमी दर के पीछे धर्म प्रेरणा के रूप में सक्रिय नहीं होता है। यह पूरी दुनिया के स्तर पर देखा जा सकता है। इसका आधार समाज के आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक विकास पर निर्भर करता है। यदि

जनसंख्या की बढ़ोतरी के पीछे धर्म की भूमिका होती तो इंडोनेशिया में वार्षिक विकास दर 1.1 प्रतिशत नहीं होती और पाकिस्तान में 2.4 प्रतिशत नहीं होती। इन दो इस्लामिक बहुल आबादी वाले देश में जनसंख्या की वार्षिक विकास दर में अंतर वहां का आर्थिक और सामाजिक विकास है। नेपाल में जनसंख्या की वार्षिक विकास दर 2.1 प्रतिशत है तो हिन्दू बाहुल्य भारत में यह विकास दर दो प्रतिशत से कम 1.93 फीसदी है। जबकि यह उल्लेखनीय है कि नेपाल दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। राजनीतिक विचारधारा और उस पर आधारित व्यवस्था जनसंख्या की विकास दर को नियंत्रित करने और कम करने में सहायक हो सकती है। जैसे चीन में वार्षिक विकास दर 0.7 प्रतिशत है।[13]

बहुविवाह प्रथा और उसका प्रचार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े कई संगठन इस्लाम में बहुविवाह प्रथा और जन्म नियंत्रण के प्रति उनकी विमुखता को आबादी बढ़ने की वजह बताते हैं। 2002 में नरेंद्र मोदी ने स्वयं सार्वजनिक तौर पर व्यंग्यात्मक रूप में 'हम पांच हमारे पच्चीस' कह कर मुस्लिमों को संदर्भित किया था। लेकिन 1961 की जनगणना के मुताबिक सबसे ज्यादा बहुविवाह आदिवासियों में 15.2 प्रतिशत, बौद्धों में 7.9 प्रतिशत, जैनियों में 6.7 प्रतिशत और हिन्दुओं में 5.8 प्रतिशत होता है। मुस्लिमों के लिए यह आंकड़ा सबसे कम 5.7 प्रतिशत रहा है। 1961 के बाद किसी जनगणना में बहुविवाह को लेकर अध्ययन नहीं किया गया।[14] ■

***वरुण शैलश** पत्रकार व शोधार्थी हैं।*

संदर्भ सूची

1.Bhagat, R.B.,Census enumeration, religious identity and communal polarization in India

2. वही

3. शैलेश, वरुण, बलौदिया, संजय, मीडिया में मुस्लिम आबादी, मार्च 2015, अंक 363.

4. वही

5. वही

6. S. Rukmini, Singh, Vijaita, Muslim Sex ratio improves further, The Hindu, Wednesday, August, 26, 2015

7. Dr. Jain, Surendra, Press Statement :Demographic Imbalance Dangerous for National Existence and Identity

8. शर्मा, हरिकिशन, 'सात राज्यों में अल्पसंख्यक हैं हिन्दू' दैनिक जागरण पेज संख्या 19, 27 अगस्त, 2015, दिल्ली संस्करण

9. वही

10 वही, शर्मा, हरिकिशन

11. Population of Christian grew by 478% in Odisha in 50 years, The Hindu, Kolkata Edition, August, 30, 2015

12. झारखंड के आदिवासी संगठनों ने धर्म पर जनगणना आंकडों पर नाखुशी व्यक्त की http://www.prabhatkhabar.com/news/jamshedpurjharkhand.tribal.organizations.census.data.on.religion.ex pressed-unhappiness/536771.html

13. वही, संदर्भ संख्या-3

14. वर्मा, के., पवन, जनसंख्या एक घृणित खेल, जनशक्ति, 28 जून-04 जुलाई, 2015, पेज संख्या-7 ■

जन मीडिया/ मास मीडिया के सदस्य बनें

संचार के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं में शोध संस्कृति के विकास के लिए जन मीडिया/मास मीडिया पहला प्रयास है, जिसका उद्देश्य 'हमारा समाज, हमारा शोध' है। इस पत्रिका को अपने बूते खड़ा करने के लिए पाठकों से अपील है कि वह इसकी वार्षिक व आजीवन सदस्यता लें। अपने मित्रों, संबंधियों, परिचितों को पत्रिका का सदस्य बनने के लिए प्रेरित करें। सदस्यता के लिए आप सदस्यता फार्म भरकर जन मीडिया/मास मीडिया कार्यालय के पते पर भेज सकते हैं। सदस्यता शुल्क का भुगतान चेक/ड्रॉफ्ट के जरिए **'जन मीडिया'** के नाम स्वीकार्य होगा। सदस्यता के लिए आप अपना नाम, पता व फोन नंबर को पोस्टकॉर्ड या ई-मेल के जरिए या एसएमएस के जरिए जन मीडिया/मास मीडिया के फोन नंबर या ई-मेल पर भेज सकते हैं। सदस्यता शुल्क को सीधे **'जन मीडिया'** के बैंक अकाउंट संख्या-21360200000710, बैंक ऑफ बड़ौदा, बादली शाखा, दिल्ली, (IFSC Code - BARB0TRDBAD) के खाते में भी जमा कराया जा सकता है। ऑनलाइन सदस्यता के लिए हमारी वेबसाइट **www.mediastudiesgroup.org.in** में **Subscriptions** पर क्लिक करें।

वार्षिक सदस्यता (व्यक्तिगत)	:	₹240
वार्षिक सदस्यता (संस्थागत)	:	₹500
सदस्यता दो वर्ष (व्यक्तिगत)	:	₹450
सदस्यता दो वर्ष (संस्थागत)	:	₹1000
सदस्यता पांच वर्ष (व्यक्तिगत)	:	₹1100
सदस्यता पांच वर्ष (संस्थागत)	:	₹2500
आजीवन सदस्यता (व्यक्तिगत)	:	₹3000
आजीवन सदस्यता (संस्थागत)	:	₹10000

दिल्ली से बाहर के चैकों के लिए ₹ 50 और जोड़कर भेजें।

संपर्क

ए-4/5, रोहिणी, सेक्टर-18, दिल्ली-110085

मो. 9968771426, 9910638355

Email : subscribe.journal@gmail.com